विद्युत स्कीमें दामोदर घाटी निगम क्षेत्र में 144 मेगावाट सहित उपर्युक्त क्षमता का 18.43 प्र. का उपयोग करती हैं। 5 जल विद्युत स्कीमें इस समय निर्माणाधीन हैं जो 60 प्र. लोड फैक्टर पर 231.78 मेगावाट क्षमता का उपयोग करेंगी। बिहार में प्रचालित और निर्माणाधीन स्कीमें ही 61.51 प्र. की कुल क्षमता का उपयोग करेंगी।

महानदी बेसिन में जल संसाधनों के लिये व्यापक योजना

3489. चौधरी हरि सिंह : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महानदी बेसिन में जल संसाधनों के प्रबन्धन के लिए व्यापक योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या उक्त व्यापक योजना के अन्तर्गत कुछ योजनाओं को कार्यान्वित करने का कार्य शुरू कर दिया गया है;

(ग) क्या राज्य सरकार ने महानदी बेसिन में बाढ़ नियंत्रण योजनाओं के लिए तत्काल वित्तीय सहायता दिए जाने की मांग की है; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) : (क) और (ख) वर्ष 1987 में अपनाई गई राष्ट्रीय जल नीति में नदी बेसिन को जल संसाधनों की आयोजना के मुख्य यूनिट के रूप में मानने की आवश्यकता को समझा गया तथा राज्यों में बहुविषयक यूनिटों की स्थापना द्वारा सिंचाई सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए जल संसाधनों के एकीकृत एवं उनके इष्टतम विकास हेतु नदी बेसिन मास्टर योजनाएं तैयार करने पर बल दिया गया है। इसके आधार पर अप्रैल, 1990 में केन्द्रीय जल आयोग द्वारा नदी बेसिन मास्टर योजनाएं तैयार करने हेतु राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को दिशानिर्देश जारी किए गये हैं। वर्तमान नीति के अनुसार, जल संसाधनों के विकास की परियोजनाओं की आयोजना, वित्तपोषण तथा क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार किया जाता है।

(ग) ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

छोटी-बड़ी परियोजनाओं को पूरा किया जाना

3490. **श्रीमती सुषमा स्वराज :**
श्री राम जेठमलानी :

क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1951 में हमारे देश में 264 लघु/बड़ी परियोजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया था और वर्ष 1992 तक उनमें से 102 परियोजनाओं को पूरा किया जा सका है;

(ख) क्या यह भी सच है कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता पैदा करने के लिये 22,956 रुपए लागत आती थी जो सातवीं योजना के दौरान बढ़कर 42,700 रुपए हो गई;

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और क्या यह भी सच है कि परियोजनाओं के निर्धारित समय पर पूरा न होने के कारण उनकी लागत में वृद्धि होती है और देश में प्रति हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ती जा रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951—56) में क्रियान्वयन के लिए शुरू की गई 44 बृहद, 169 मध्यम और 12 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण सिंचाई परियोजनाओं में से, मार्च 1992 तक 40 बृहद, 168 मध्यम और 12 विस्तार/नवीकरण/आधुनिकीकरण परियोजनाएं पूरी की गई। 4 बृहद परियोजनायें नामतः भाखड़ा, तुंगभद्रा बांध तथा नागार्जुन सागर और बसंत तथा रामेश्वर

घाटी निगम की सिंचाई प्रणाली और एक मध्यम परियोजना नाम भीमसागर आठवीं योजना में आगे लाई गई है, और इनमें से, भाद्रा, तुंगभद्रा बांध और बायां तटनहर एवं भीमसागर परियोजना पर कार्य अधिकांशतः पूरा हो गया है।

(ख) और (ग) छठी और सातवीं योजना के दौरान वृहद और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं के जरिए एक हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने पर व्यय की गई औसत राशि क्रमशः 22,000 रुपए और 50,000 रुपए रही। इस परियोजना को निर्धारित समय के अन्दर पूरा न किए जाने का एक महत्वपूर्ण कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हो जाना रहा है।

(घ) देश में सिंचाई परियोजनाओं की लागत में वृद्धि के मुख्य कारण ये हैं: निधियों के अपर्याप्त प्रावधान के कारण निर्धारित समय में उनका पूरा न होना, कार्यान्वयन के दौरान डिजाइन के क्षेत्र में परिवर्तन, वन और निजी भूमि के अधिग्रहण में आनेवाली समस्याएं, विस्थापितों का पुनर्वास तथा पुनर्स्थापन, जन आन्दोलन, श्रम, ठेके संबंधी तथा तकनीकी समस्याएं आदि। आठवीं योजना की नीति में चालू परियोजनाओं को पूरा करने पर बल दिया गया है तथा योजना आयोग ने महत्वपूर्ण परियोजनाओं को समय पर पूर्ण करना सुनिश्चित करने के लिए परिव्यय निर्धारित करना शुरू कर दिया है।

LOANS FROM THE WORLD BANK

3491. SHRI PRAMOD MAHAJAN : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) what are the details of irrigation projects for which Government have taken loans from the World Bank and other agencies during the Seventh and Eighth Five Year Plan period;

(b) what is the amount of loan obtained and utilised on each of the World Bank assisted projects as on 30th September, 1993;

(c) what is the unutilised credit and what are the reasons for which the credit has not been utilised in respect on each project;

(d) what are the details of projects which were started during the Seventh Plan period and postponed to Eighth Plan and what is the progress of each project including the details of expenditure incurred so far; and

(e) how many of these projects are likely to be postponed to Ninth Plan and the reasons therefor ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGAN) : (a) The Government have taken about US $ 2364 million from the World Bank and other agencies as financial assistance for implementation of 71 irrigation projects during the Seventh and Eighth Five Year Plan period uptil September, 1993.

(b) and (c) Information is given in the statement. (*See* below) As regards utilisation of assistance, there have been some instances of under utilisation of the external assistance in some projects. The main reasons for this are :—

(i) Initial slippage in the implementation of the project.

(ii) Delay in declaring loan|credit effectiveness by the World Bank on account of Non-availability of satisfactory action plan on resettlement of rehabilitation.

(iii) Delay in approval of Local Competitive Bidding and International Competitive Bidding Packages by the World Bank.

(iv) State Government's financial crunch.

(v) Untimely release of allotted funds to the projects.

(vi) Subsequent cut in annual plan budget of the project.